National Diary Project-II (Operation Flood-III) which is being financed by World Bank and the European Economic Community (EEC), dairy developmental activities are funded in the State.

जम्मू और काश्मीर में सेब की फसल का संरक्षण

3590. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जम्मू और कश्मीर में सेब की फसल के संरक्षण के लिए और वहां सेब उत्पाद की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : जम्मू और कश्मीर में सेब की फसल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सेबों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करके सहायता करना;

(2) जम्मू और काश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन निगम ने किसानों से उनके उत्पाद को राज्य से बाहर बेचने के लिए खरीदने हेतु कदम उठाए हैं । इसी प्रकार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भी जम्मू और कश्मीर से सेबों के विपणन का कार्य करने तथा फलों की पैकिंग के लिए गत्ते के डिब्बे (कार्टोन्स) तथा पेपर ट्रे की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है;

(3) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड फलों की ग्रेडिंग करने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण देने पर भी सहमत हो गया है, ताकि किसानों को अधिक कीमत प्राप्त हो सके;

(4) चालू मौसम के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा, जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन निगम तथा नेफेड के सहयोग से लगभग 75,000 मीटरी टन फलों की कुल खरीद की जाएगी ।

मुस्लिम समुदाय के हरिजनों द्वारा हाथ में मैला उठाने का कार्य किया जाना

3591. **डा. अबरार अहमद खान** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे हरिजन हैं, जो हाथ से गन्दगी साफ करने और मैला उठाने का कार्य करते हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही उनकी संख्या कितनी है और वे कहां रहते हैं; और

(ख) क्या इन मुस्लिम हरिजनों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता, शिक्षा में सहायता और उनके बच्चों को रोजगार या आरक्षण सुविधा दी गई है, उन्हें भूमि या आवास का आवंटन, उन्हें अपना व्यवसाय बदलने के लिए ऋण या कृषि भूमि का आवंटन किया गया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मुस्लिम समुदाय का एक विशेष वर्ग भी अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत है । सफाई कर्मचारियों की विमुक्ति की एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वयनाधीन है, जिसमें मौजूदा शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने और विस्थापित सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की व्यवस्था है । इस योजना के अन्तर्गत गैर अनुसूचित जाति समुदायों से सम्बधित सफाई कर्मचारी भी विभिन्न कामधन्धों/व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं । गैर अनुसूचित जाति मुक्त सफाई कर्मचारियों को पुनर्वास हेतु सामान्य

क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता दी जाती है । अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों अर्थात् चमड़ा उतारने वालों चर्मशोधकों तथा झाड़ूबरदारों को जो परम्परागत रूप से सफाई कार्य से जुड़े हैं के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की एक अन्य केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वयनाधीन है । इस योजना के अन्तर्गत, कक्षा छठी से आठवीं के छात्रों को 200/- रु. प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा नौवीं तथा दसवीं के छात्रों को 250/- रु. प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । 1989-90 के दौरान इस योजना के लिए एक करोड़ रुपये तथा 1990-91 के लिए 3 करोड रुपये का आवंटन किया गया । मण्डल आयोग की रिपोर्ट में कुछ गैर हिन्दू समुदायों को भी उनके द्वारा तैयार किए गए मानदण्डों के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के रूप में शामिल किया गया है । सरकार ने प्रथम चरण में उन जातियों या समुदायों को अपनाने का निर्णय लिया है, जो मण्डल सूची के साथ-साथ राज्य सूचियों दोनों में सांझे हैं और 7-8-1990 से भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

मुस्लिमों के संबंध में जैसा कि पूछा गया है अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

Number of seats in general compartments of express trains leaving Delhi stations

3592. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total number of seats in general compartments of the express tarins leaving Delhi railway stations for Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh and Orissa; and

(b) the total number of tickets sold pertaining to the general compartments of the trains cited above, during the year 1988 ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) As against an average of 11967 seats per day in General Compartments of express tarins leaving, Delhi, New Delhi and Hazrat Nizamuddin Railway stations for Madhya Pradesh, Bihar Rajasthan, Uttar Pradesh and Orissa, an average of 22450 tickets were issued per day towards these States from these stations during the year 1988. Under the provisions of the Railways Act, 1989, ticket is issued on payment of fare to any person desirous of travelling on a railway. The ticket is deemed to have been issued subject to the condition of availability of accommodation in the train for that class of carriage.

Setting up of a new Suburban Railway Station between Mulund and Bhandup station

3593. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have reconsidered the proposal of setting up a New Suburban Railway Station in between Mulund and Bhandup station of the Central Railway Suburban Network in Bombay; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) The proposal for opening of a new halt station between Mulund and Bhandup station has been examined. This has neither been found operationally feasible nor financially justified.

Concession to vanaspti industry

3594. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) what is the total value of the concession given to vanaspati industry during